रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, शुक्रवार सितम्बर 3, 1997/आश्विन 11, 1919

No. 195] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 1997/ASHVIN 11, 1919

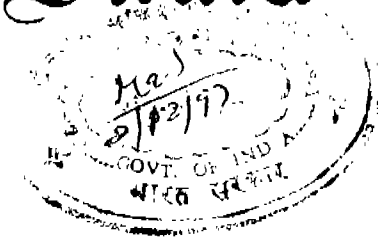

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

शुद्धि -पत्र

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1997

विषय : प्रबंध शिक्षा सहित उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी और गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा शुल्क निर्धारण करने की नीति ।

सं.एफ. 20-43/96-डेस्क (यू) :—राष्ट्रपति,भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-1 संख्या 50 दिनांक 18 मार्च, 1997 में प्रकाशित उपर्युक्त विषय पर विभाग के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष अधिसूचित करते हैं :

(1) उप पैरा 6.2 के खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

(घ) विश्वविद्यालय जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा उनके अनुरक्षण या विकास व्यय के लिए सांविधिक अनुदान वितरण निकायों से अनुदान नहीं ले रहे अथवा किसी निजी न्यास या सोसायटी तथा किसी राज्य सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित विश्वविद्यालय; और

(2) परिणामत: खण्ड (घ) उप पैरा 6.4 की पंक्तियों तथा 2 को इस प्रकार से पढ़ा जाए :—

उप पैरा 6.2 (घ) में संदर्भित सम-विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाने वाला शिक्षा शुल्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थाई समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

पी.आर. दासगुप्ता, सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd October, 1997

Subject : Policy on Fee Fixation in Private Unaided Educational Institutions imparting Higher and Technical Education includ- ing Management Education.

No. F. 20-43/96-Desk (U) :—President is pleased to notify the following amendments in the Department's Resolution on the subject cited, published in The Gazette of India, Extraordinary Part I Section 1 number 50 dated the 18th March,1997:

(1) After Clause (c) of sub-para 6.2, the following be added:

(d) Universities, not receiving grant-in-aid from the Central or State Government or their Statutory grant disbursing bodies for their maintenance or development expenditure or Universities eastablished as a joint venture between a private trust or society and a State Government; and

(2) Consequently, Lines 1 and 2 of Clause (d) sub-para 6.4 be read as under :

Fee chargeable by Institutions deemed to be universities and the Universities referred in Sub-para 6.2 (d) will determined by a Standing Committee of the University Grants Commission consisting of :

P.R. DASGUPTA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997